>

Title: Need to provide civic amenities in colonies settled on Government Land.

श्री गोपाल शेट्टी (**मुम्बई उत्तर**): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने 2022 तक सभी को अपने हक का पक्का घर देने का वादा किया है। सभी राज्य सरकारों ने इस ओर अपने कदम बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 2011 तक महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों घर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकार की जो जमीनें हैं, उदाहरण के तौर पर जो फॉरेस्ट लैण्ड है, बाकी अलग-अलग प्रकार की जमीनें सभी राज्यों में होती हैं, रेलवे की जमीन है, बीपीटी लैण्ड है, वहां पर आज भी घर बनाने की परमीशन नहीं दी जाती है, सीवर लाइन डालने के लिए विरोध किया जाता है, टॉयलेट बनाने के लिए भी विरोध किया जाता है, यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स भी नहीं दिए जाते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि आने वाले 15 अगस्त से पहले संबंधित मंत्री को इस बारे में एक सर्कुलर पूरे देश भर के लिए निकालना चाहिए। जब देश के प्रधान मंत्री एक मैसेज देते हैं तो लोगों में भी उम्मीद जागती है कि अपना घर अच्छा और ठीक से बनाएं, इस प्रकार का वे प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को जितनी भी जगह चाहिए, प्राइवेट फॉरेस्ट के माध्यम से कायदे के हिसाब से पर्याप्त जगह लोगों को देकर, जमीन मालिक को जमीन का पैसा देकर सारी जमीन इन्कलूड करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा जब तक नहीं होता है, तब तक वहां रहने वाले लोगों के जीवन में एक नई खुशहाली आए, वे अपना घर अच्छे तरीके से बना पाएं, उनको शौचालय की सुविधा मिले, उनको सीवर लाइन और इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन्स मिलें, इस प्रकार की व्यवस्था हमें आने वाले 15 अगस्त से पहले करना चाहिए। हम इस वर्ष महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी

मना रहे हैं, इस अवसर पर यह एक तोहफा पूरे देश के लोगों को दें। इस प्रकार की मांग, मैं आपके माध्यम से, सरकार से करता हूं। धन्यवाद।

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव (**गुना**): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष: रोज ही बोल रहे हो, यह भी तो कहो, माननीय सदस्य।